

अनुच्छेद 370 हटाने पर सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय

प्रलिमिंस के लयि:

[अनुच्छेद 370](#), [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वशिष दरजा](#), [केंद्रशासति प्रदेश](#), [असममति संघवाद](#), [भारत की संवधिान सभा](#), [परगिरहण पत्र](#), [अनुच्छेद 371](#), [371A- I](#), [अनुच्छेद 367](#), [वधिानसभा](#) ।

मेन्स के लयि:

[केंद्रशासति प्रदेश जममू-कश्मीर](#) की राजनीति एवं अरथवयवस्था पर सर्वोच्च न्यायालय के नरिणय की प्रासंगकिता ।

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने संवधिान के [अनुच्छेद 370](#) में संशोधन करने के केंद्र सरकार के वर्ष 2019 के कदम पर अपना नरिणय सुनाया । इस नरिसन ने पूर्ववर्ती राज्य जममू-कश्मीर को प्रदत्त वशिष दरजा समाप्त कर दया था । न्यायालय ने [अनुच्छेद 370](#) को रद्द करने वाले संवधिानकि आदेश को वैध माना ।

सर्वोच्च न्यायालय का हालया फैसला क्या है?

■ जममू-कश्मीर के पास संप्रभुता नहीं थी:

- सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 370 और जममू-कश्मीर के संवधिान में इस बात को दर्शाने के लयि बहुत सारे सबूत हैं कि कश्मीर के संबंध में अपनी संप्रभुता को छोड़ने के लयि वलिय समझौता आवश्यक नहीं था ।
- [अनुच्छेद 370\(1\)](#) भारत के संवधिान के [अनुच्छेद 1](#) (जहाँ जममू-कश्मीर को भाग III राज्य के रूप में सूचीबद्ध कया गया था) को बना कसी संशोधन के लागू करता है ।

- जममू-कश्मीर संवधिान की धारा 3 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "जममू-कश्मीर राज्य भारत संघ का अभनिन अंग है और रहेगा ।"

- भारतीय संवधिान की धारा 147 ने धारा 3 में कसी भी संशोधन पर रोक लगा दी, जससे प्रावधान पूरण हो गया ।

- इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि भारत का संवधिान "देश का सर्वोच्च प्रशासकीय दस्तावेज है ।" इसके अलावा जममू-कश्मीर संवधिान की प्रस्तावना में "संप्रभुता के संदर्भ का स्पष्ट अभाव" दखिता है ।

■ अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान है:

- सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर भरोसा कया कि संवधिान नरिमाताओं ने [अनुच्छेद 370](#) को भाग XXI में नहिति अस्थायी और संक्रमणकालीन प्रावधानों के साथ रखा था ।
- फरि इसने बताया कि वलिय पत्र (IoA) ने इसे "बहुत हद तक स्पष्ट" कर दया है कि [अनुच्छेद 1](#), जसमें कहा गया है कि "इंडया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा", पूरी तरह से जममू-कश्मीर पर लागू होता है ।

■ राष्ट्रपति शासन के तहत उदघोषणा की संवधिानकि वैधता:

- सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सहमति वयकत की कि राष्ट्रपति के पास "राज्य वधिानसभा के वधिटन करने सहति अपरविरत्नीय परविरत्तन" करने की शक्ति है एवं राष्ट्रपति की शक्तियों को "न्यायकि और संवधिानकि जाँच" द्वारा नरिंत्तरति रखा जाता है ।

■ जममू-कश्मीर का संवधिान नषिकरयि है:

- न्यायालय ने माना कि अब जममू-कश्मीर के संवधिान का अस्तत्ति में रहना आवश्यक नहीं है, इसके माध्यम से भारतीय संवधिान के केवल कुछ प्रावधान ही जममू-कश्मीर पर लागू होते हैं ।

- भारत के संवधिान को संपूरण रूप से जममू-कश्मीर राज्य में लागू करने का अंतरनहिति लेकनि आवश्यक परणाम यह है कि राज्य का संवधिान नषिकरयि है ।

■ मानवाधिकारों के प्रावधान के लयि एक सत्य और सुलह आयोग का गठन:

- सर्वोच्च न्यायालय ने सफिरशि की कि संघ राज्य और गैर-राज्य दोनों अभकिरत्ताओं द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच के लयि

एक "सत्य और सुलह आयोग" स्थापति किया जाए, ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद के बाद राज्य और गैर-राज्य दोनों पक्षों द्वारा मानवाधिकारों के उल्लंघन की जाँच की। इस आयोग का प्रयोग समयबद्ध होना चाहिये।

जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा क्या था?

परिचय:

- 5 अगस्त, 2019 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 370(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए संविधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 जारी किया।
 - इसके ज़रिये भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 में ही संशोधन किया है (उसे रद्द नहीं किया है)।
- इसके द्वारा भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज्य तथा भारतीय संघ के बीच संबंधों में नाटकीय रूप से बदल दिया है।

पृष्ठभूमि:

- जम्मू-कश्मीर को छूट प्रदान करते हुए 17 अक्टूबर, 1949 को एक 'अस्थायी प्रावधान' के रूप में अनुच्छेद 370 को भारतीय संविधान में शामिल किया गया, इससे जम्मू-कश्मीर को अपना संविधान बनाने की अनुमति प्राप्त हुई और राज्य में भारतीय संसद की वधायी शक्तियों के प्रयोग पर प्रतिबंधित लगा दिया गया।
 - इसे एन गोपालस्वामी अयंगर ने संविधान के मसौदे में अनुच्छेद 306A के रूप में पेश किया था।

अनुच्छेद 370:

- भारतीय संविधान के कौन-से अनुच्छेद राज्य पर लागू होने चाहिये इसकी सफ़ाई करने का अधिकार जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा को प्रदान किया गया।
 - राज्य के संविधान का मसौदा तैयार करने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। अनुच्छेद 370 का खंड 3 भारत के राष्ट्रपति को इसके प्रावधानों और दायरे में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है।
- अनुच्छेद 35A का स्रोत अनुच्छेद 370 है और इसे जम्मू-कश्मीर संविधान सभा की सफ़ाई पर वर्ष 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से पेश किया गया था।
 - अनुच्छेद 35A जम्मू-कश्मीर विधानसभा को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेष अधिकारों तथा विशेष लाभों को परामर्श करने का अधिकार देता है।
 - यह भारत के संविधान के परिशिष्ट 1 में परिलक्षित होता है।
- कई राज्यों को अलग-अलग संवैधानिक गारंटी प्रदान की गई है। इन्हें आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिये अनुच्छेद 371, 371A- I में संशोधित किया गया है।

नोट:

भारतीय संविधान शेष भारत के लिये संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राज्य की शक्ति को बढ़ाने अथवा उस पर अंकुश लगाने के लिये अनुच्छेद 367 में एक वसित प्रक्रिया निर्धारित करता है। हालाँकि जम्मू-कश्मीर के लिये संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत केवल कार्यकारी कार्रवाई ही पर्याप्त होगी।



वर्ष 2019 के आदेश द्वारा किये गए प्रमुख परिवर्तन क्या हैं?

- **संवधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019:**
 - वर्ष 1954 के राष्ट्रपति आदेश को संवधान (जम्मू-कश्मीर पर लागू) आदेश, 2019 द्वारा प्रतस्थापित कर दिया गया है।
 - इसके बाद संसद द्वारा पारित [जम्मू और कश्मीर पुनर्रगठन अध्याय \(2019\)](#) जम्मू तथा कश्मीर राज्य को दो नए केंद्रशासित प्रदेशों (UT): [जम्मू-कश्मीर](#) तथा [लद्दाख](#) में विभाजित करता है।
 - ऐसा पहली बार है कि किसी राज्य को केंद्रशासित प्रदेश में बदल दिया गया है।
 - वर्तमान में जम्मू-कश्मीर राज्य की छह लोकसभा सीटों में से पाँच केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के पास रहेंगी, जबकि एक का आवंटन लद्दाख को किया जाएगा।
 - दिल्ली और पुद्दुचेरी की तरह ही केंद्रशासित प्रदेश [जम्मू-कश्मीर](#) में एक [वधानसभा](#) होगी।
 - लद्दाख बना वधानसभा वाला केंद्रशासित प्रदेश होगा।
 - कश्मीर में अब राज्यपाल नहीं, बल्कि दिल्ली अथवा पुद्दुचेरी की तरह एक उपराज्यपाल होगा।
- **जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा:**
 - जम्मू-कश्मीर वधानसभा का कार्यकाल छह वर्ष का नहीं, बल्कि पहले की ही तरह पाँच वर्ष का होगा।
 - जम्मू-कश्मीर 2019 अध्याय की धारा 32 में प्रस्तावित है कि वधानसभा "सार्वजनिक व्यवस्था" और "पुलिस" से संबंधित राज्य के विषयों को छोड़कर राज्य तथा समवर्ती सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है।
 - यह [संवधान के अनुच्छेद 239A](#) के समान है जो केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी तथा दिल्ली पर लागू होता है।
 - हालाँकि [अनुच्छेद 239AA](#) के सम्मिलन तथा [69वें संवधानिक संशोधन](#) के आधार पर दिल्ली वधानसभा राज्य सूची की प्रविष्टि 18 के मामलों, अर्थात् भूमि पर कानून नहीं बना सकती है।
 - जम्मू-कश्मीर के मामले में वधानसभा भूमि पर कानून बना सकती है।
- **जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति समाप्त:**
 - जम्मू-कश्मीर का अब कोई अलग संवधान, झंडा अथवा राष्ट्रगान नहीं होगा।
 - जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता नहीं होगी।
 - चूँकि जम्मू-कश्मीर का नया केंद्रशासित प्रदेश भारतीय संवधान के अधीन होगा, इसलिये इसके नागरिकों को अब भारतीय संवधान में नहित मौलिक अधिकार प्राप्त होंगे।
 - [अनुच्छेद 360](#), जिसका उपयोग वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिये किया जा सकता है, अब भी लागू होगा।
 - संसद द्वारा पारित सभी कानून जम्मू-कश्मीर में लागू होंगे, जिनमें [सूचना का अधिकार अधिनियम](#) तथा [शिक्षा का अधिकार अधिनियम](#) भी शामिल हैं।
 - [भारतीय दंड संहिता](#), जम्मू-कश्मीर की रणबीर दंड संहिता की जगह लेगी।
 - [अनुच्छेद 35A](#), जो [अनुच्छेद 370](#) के प्रावधानों से उत्पन्न हुआ है, अमान्य है।

नोट:

जम्मू-कश्मीर का संघ के साथ ऐतिहासिक रूप से एक अखंडा रश्ति रहा है। जम्मू-कश्मीर तथा संघ के बीच कोई वलिय समझौता नहीं हुआ था, बल्कि यह केवल [वलिय पत्र \(इंस्ट्रुमेंट ऑफ एक्सेशन- IoA\)](#) था, इसलिये संप्रभुता का कोई हस्तांतरण नहीं है एवं राज्य की स्वायत्तता का प्रावधान था। [IoA](#) बाह्य संप्रभुता से संबंधित है। कुछ अपवादों के अतिरिक्त बाह्य संप्रभुता समाप्त हो गई है। [CJI](#) ने हालिया नरिण्य में कहा कि [IoA](#) पर हस्ताक्षर के बाद जम्मू-कश्मीर की कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं है।

अनुच्छेद 370 के नरिकरण में वभिन्न वधिक चुनौतियाँ क्या थीं?

- **सांवधानिक चुनौतियाँ:**
 - राष्ट्रपति के आदेश में जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को समाप्त करने की मांग की गई थी, [अनुच्छेद 370 \(3\)](#) के अनुसार, राष्ट्रपति को इस तरह के बदलाव के लिये [जम्मू-कश्मीर की संवधान सभा की अनुशंसा की आवश्यकता](#) होगी।
 - हालाँकि वर्ष 2019 के राष्ट्रपति आदेश द्वारा [अनुच्छेद 367](#) में एक उप-खंड जोड़ा गया, जो नमिनलखित पदों को प्रतस्थापित करता है:
 - "जम्मू-कश्मीर की संवधान सभा" का आशय "जम्मू-कश्मीर की वधानसभा" से है।
 - "जम्मू-कश्मीर सरकार" का तात्पर्य "जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल का मंत्रपरिषद की सहायता एवं सलाह पर कार्य करने" से है।
 - सरकार ने [सांवधानिक संशोधन](#) लाए बना [अनुच्छेद 370](#) के तहत स्वायत्तता को कम करने की मांग की, जिसके लिये संसद में दो-तर्हिई बहुमत की आवश्यकता होती है।
 - इस प्रावधान को सर्वोच्च न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी गई कि इसने केवल राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से भारतीय संवधान में [अनुच्छेद 35A](#) को जोड़ा।
 - जम्मू-कश्मीर को केंद्रशासित प्रदेश में बदलना [अनुच्छेद 3](#) का उल्लंघन है क्योंकि राज्य वधानसभा द्वारा अध्याय को राष्ट्रपति के पास नहीं भेजा गया था।
 - राज्य के पुनर्रगठन में राष्ट्रपति के आदेश के लिये राज्य सरकार की सहमति की भी आवश्यकता होती है। चूँकि जम्मू-कश्मीर वर्तमान में राज्यपाल शासन के अधीन है, इसलिये राज्यपाल की सहमति को सरकार की सहमति माना जाता है।

■ **संघवाद का मुद्दा:**

- वलिय पत्र दो संप्रभु देशों के बीच संधि की तरह था, जनिहोंने एक साथ कार्य करने का नरिणय लया था ।
- **संतोष कुमार बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य एवं अन्य, 2017** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐतिहासिक कारणों से जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था ।
- **एसबीआई बनाम ज़फर उललाह नेहरू, 2016** में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जम्मू- कश्मीर की संवधान सभा की सहमति के बिना अनुच्छेद 370 को नरिस्त नहीं कया जा सकता है ।

अनुच्छेद 370 हटने के पश्चात् जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा के क्या हालात हैं?

■ **पथराव और उग्रवाद की घटनाओं में कमी:**

- **राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA)** जैसी केंद्रीय एजेंसियों की बढ़ती सुरक्षा उपस्थिति और कार्रवाई के कारण पथराव के मामलों में कमी आई ।
- पथराव की घटनाओं की संख्या वर्ष 2019 के 618 से घटकर वर्ष 2020 में 222 हो गई ।
- सुरक्षा बलों के घायल होने की घटनाएँ 2019 के 64 से घटकर 2021 में 10 हो गई ।

■ **नागरिकों के घायल होने की घटनाओं में कमी:**

- पेलेट गन और लाठीचार्ज से नागरिक के घायल होने की संख्या 339 (2019) से घटकर 25 (2021) हो गई ।
- जम्मू-कश्मीर में कानून और व्यवस्था में भी सुधार हुआ क्योंकि 2022 में कानून और व्यवस्था की केवल 20 घटनाएँ दर्ज की गई ।

■ **उग्रवादियों और ओवर-ग्राउंड वर्करों की गरिफ्तारियाँ (OGWs):**

- आतंकवादी समूहों के OGW की गरिफ्तारियाँ 2019 के 82 से बढ़कर 2021 में 178 हो गई ।
- पिछले 10 महीनों की तुलना में अगस्त 2019 से जून 2022 तक आतंकवादी कृत्यों में 32% की गरिवट आई है ।

FEWER INJURIES, DEATHS AMONG SECURITY FORCES

Incidents	52 months before Aug 5, 2019	52 months after Aug 5, 2019
Terrorist-initiated incidents	765	455
Attacks on civilians	193	156
Civilian casualties	234	131
Civilians injured	1,300	422
Encounters	390	338
Security forces injured	1,098	334
Security forces killed	355	125

अनुच्छेद 370 के नरिस्तीकरण पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने किस प्रकार प्रतिक्रिया दी?

■ **पाकस्तान और मुसलमि विश्व/जगत:**

- पाकस्तान ने जम्मू-कश्मीर पर भारतीय संवधान की सर्वोच्चता को मानने से इनकार कर दिया ।
- **इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC)** ने "क्षेत्र की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विवादित स्थिति को बदलने के उद्देश्य से 5 अगस्त, 2019 से उठाए गए सभी अवैध और एकतरफा उपायों" को उलटने के लिये पुनः आह्वान कया ।

■ **चीन:**

- चीन के अनुसार वह "भारत द्वारा एकतरफा और अवैध रूप से स्थापित तथाकथित केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख" को मान्यता नहीं देता है तथा चीन-भारत सीमा का पश्चिमी खंड हमेशा चीन का हिससा रहा है ।

■ **संयुक्त राज्य अमेरिका:**

- इसने जम्मू-कश्मीर में हरिस्त और प्रतर्बिंधों पर चर्चा व्यक्त की, लेकिन सभी पक्षों से सीमा पार आतंकवाद से नपिटने के लिये "दृढ़ व मज़बूत कदम उठाने" सहित **नयितरण रेखा** पर शांति एवं स्थिरता बनाए रखने का भी आह्वान कया ।

■ **यूरोपीय संघ:**

- इसने भारत और पाकस्तान से पुनः संवाद/वार्ता शुरू करने का आह्वान कया तथा कश्मीर पर द्वपिक्षीय समाधान के लिये समूह के समर्थन को दोहराया ।

■ रूस:

- रूस ने रेखांकित कथिा कऱि **परविरतन "भारत गणराज्य के संवधिन के ढाँचे के भीतर"** कथि गए थे। मॉस्को ने जममू-कश्मीर मुद्दे की "द्विपक्षीय" प्रकृति पर भी बल दथिा और **शमिला समझौते (वर्ष 1972)** व **लाहौर घोषणा (वर्ष 1999)** का उल्लेख कथिा।

आगे की राह

- कश्मीर के उत्थान के लथि **3E (शकषिा, रोजगार और नथिोजनीयता)** के लथि **10 साल की रणनीति** लागू की जानी चाहथि।
- जममू-कश्मीर में '**शून्य-आतंकवादी घटना**' की योजना 2020 से लागू है और 2026 तक सफल होगी।
- कश्मीर में वैधता के संकट के समाधान के लथि **अहसिा और शांति का गांधीवादी मार्ग** अपनाया जाना चाहथि।
- सरकार **सभी कश्मीरथिों तक एक व्यापक आउटरीच कार्यक्रम** शुरू करके अनुच्छेद 370 पर कार्रवाई से उत्पन्न चुनौतथिों को कम कर सकती है।
- इस संदर्भ में कश्मीर समाधान के लथि अटल बहिरिा वाजपेथिी का **कश्मीरथित, इंसानथित और जमहूरथित (कश्मीर की समावेशी संस्कृति, मानवतावाद एवं लोकतंत्र)** का संस्करण राज्य में सुलह की ताकतों की आधारशला बनना चाहथि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. सथिाचनि हमिनद कहाँ सथति है? (2020)

- (a) अकसाई चनि के पूरव में
- (b) लेह के पूरव में
- (c) गलिंगटि के उत्तर में
- (d) नुबरा घाटी के उत्तर में

उत्तर: (d)

प्रश्न . नमिनलखिति में से कौन सा सबसे बड़ा (क्षेत्रफल के अनुसार) लोकसभा नरिवाचन क्षेत्र है? (2008)

- (a) काँगड़ा
- (b) लददाख
- (c) कच्छ
- (d) भीलवाड़ा

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. भारतीय संवधिन का अनुच्छेद 370, जसिके साथ हाशथिा नोट "जममू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध" लगा हुआ है, कसि सीमा तक अस्थायी है? भारतीय राज-व्यवस्था के संदर्भ में इस उपबंध की भावी संभावनाओं पर चर्चा कीजथि। (2016)

प्रश्न. आंतरकि सुरक्षा और नरिथितरण रेखा (LoC) सहति म्याँमार, बांग्लादेश और पाकसितान सीमा पार अपराधों का वशिलेष्ण कीजथि। वभिनिन सुरक्षा बलों द्वारा इस संदर्भ में नभिराई गई भूमकिा की भी वविचना कीजथि। (2020)

प्रश्न. जममू-कश्मीर में 'जमात-ए-इस्लामी' पर पाबंदी लगाने से आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं (ओ.जी.डब्ल्यू.) की भूमकिा ध्यान का केंद्र बन गई है। उपप्लव (बगावत) प्रभावति क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुँचाने में भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं द्वारा नभिराई जा रही भूमकिा का परीक्षण कीजथि। भूमि-उपरि कार्यकर्त्ताओं के प्रभाव को नषिप्रभावति करने के उपायों की चर्चा कीजथि। (2019)